



# PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL

The global union federation of workers in public services

## मौद्रिक नीति पर पुनर्विचार

हिन्दी



मौद्रिक नीति के बारे में यह नीति संक्षेप<sup>1</sup> डॉ. अनीस (अनीसउज्जमान) चौधरी<sup>2</sup> द्वारा लिखे गए एक पेपर से ली गई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्ताव "COVID-19 संकट से एक मानव-केंद्रित तरीके से निपटने के लिए समावेशी, टिकाऊ और लचीली कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान" को लागू करने के लिए सरकारों को जो कदम उठाने चाहिए उनका विवरण दिया गया है। यह नीति संक्षेप उन उपायों की श्रृंखला के नीति संक्षेपों का हिस्सा है जो सरकारें उस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अपना सकती हैं और जिसमें प्रस्ताव, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीति का एक सिंहावलोकन शामिल है। नीति संक्षेप का उद्देश्य प्रस्ताव को लागू करने के लिए ट्रेड यूनियनों की वकालत के काम का समर्थन करना और न्यायसंगत, टिकाऊ और रोजगार से भरपूर रिकवरी को बढ़ावा देने वाली कोविड रिकवरी योजनाएं बनाने में मदद करना है।

### अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्ताव का परिचय

प्रस्ताव, जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया, और यह नवउदारवादी व्यापक आर्थिक और औद्योगिक नीतियों से दूर जाने की आवश्यकता का संकेत देता है और सरकारों द्वारा रोजगार-समृद्ध रिकवरी योजना बनाने और प्रोत्साहित करने, काम करने की स्थिति में सुधार करने और सम्मानजनक कार्य, लैंगिक समानता और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचानता है। यह एक प्रमुख समझौता है जो सरकारों द्वारा निम्नलिखित को अपनाया जाना आवश्यक बनाता है:

i. सहायक व्यापक आर्थिक, राजकोषीय और औद्योगिक नीतियां जो समानता और स्थिरता को भी बढ़ावा देती हैं;

<sup>1</sup> चौधरी, ए 2022, व्यापक-आधार वाली, रोजगार-समृद्ध रिकवरी के लिए सहायक व्यापक आर्थिक और औद्योगिक नीतियां, पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल, <<https://publicservices.international/resources/publications/supportive-macroeconomic-and-industrial-policies-for-a-broad-based-job-rich-recovery?lang=en&id=13076>>

<sup>2</sup> सहायक प्रोफेसर, बिजनेस स्कूल ऑफ वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और पूर्व निदेशक, यूएन-ईएससीएपी मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट डिवीजन।

और

e. राजकोषीय, मौद्रिक और व्यापारिक और निवेश नीतियों को बढ़ावा देना, जिनका उद्देश्य समावेशी, टिकाऊ और लचीला आर्थिक विकास के साथ ही पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चुने गए रोजगार और सम्मानजनक कार्य हासिल करना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शताब्दी घोषणा में निर्धारित मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के संभावित लाभकारी व्यापक आर्थिक प्रभावों की समझ में सुधार करना भी शामिल है।

इसका मतलब यह है कि COVID-19 रिकवरी योजनाओं के हिस्से के रूप में, सरकारों को नवउदारवादी आर्थिक सिद्धांतों की ओर नहीं लौटना चाहिए, जो 1980 के दशक से आर्थिक नीतियों में प्रभावी रही हैं। सरकारों को इसके बजाय असमानताओं को कम करने, जलवायु संकट को दूर करने और COVID-19 से रोजगार-समृद्ध, समावेशी, टिकाऊ और लचीला रिकवरी हासिल करने के लिए प्रगतिशील मौद्रिक, राजकोषीय और औद्योगिक नीतियां तैयार करनी चाहिए। सरकारें वैश्विक मौद्रिक नियमों को संबोधित करने के लिए भी सहमत हैं जिनका उच्च ऋण स्तरों का अनुभव करने वाले देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

c. संकट के संबंध में राजकोषीय और मौद्रिक नीति के क्षेत्र में कटौती या अस्थिर बाहरी ऋण दायित्व का अनुभव करने वाले विकासशील देशों के समर्थन के माध्यम से वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देता है

## मौद्रिक नीति क्या है?

मौद्रिक नीति से तात्पर्य उन नीतियों के समूह से है जो देश अर्थव्यवस्था के भीतर धन, ऋण और ब्याज दरों की आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए अपनाते हैं। अधिकांश देशों में मौद्रिक नीति सरकार द्वारा या कानून के माध्यम से निर्धारित व्यापक उद्देश्यों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य अक्सर कीमतों और आर्थिक स्थिरता के आसपास केंद्रित होते हैं, फिर भी कई बैंकों को रोजगार में वृद्धि और अन्य उद्देश्यों पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय बैंक कई नीतिगत साधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, वे (i) खुदरा/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार लेने के लिए आधार ब्याज दर में परिवर्तन कर सकते हैं; (ii) बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंकों में रखी जाने वाली आरक्षित निधि की राशि में बदलाव कर सकते हैं; (iii) बॉन्ड जैसी संपत्तियां खरीद या बेच सकते हैं (इसे खुला बाजार संचालन और मात्रात्मक सरलता के नाम से जाना जाता है); (iv) अपने मूल्य को प्रभावित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से घरेलू या विदेशी मुद्राएं खरीद सकते हैं।

कार्रवाइयां (i) और (ii) खुदरा बैंकों की कर्ज देने या क्रेडिट बनाने की क्षमता पर प्रभाव डालती हैं। जब आधार दर या आरक्षित कोष की राशि को कम किया जाता है, तो खुदरा बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सकता है।

चूंकि 1980 के दशक और नवउदारवाद के प्रसार के बाद से, केंद्रीय बैंक विशेष रूप से मुद्रास्फीति की दर पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं और इसलिए मौद्रिक नीति मुख्य रूप से "मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने" या मुद्रास्फीति को पूर्व निर्धारित स्तर या सीमा के भीतर रखने के आसपास ही बनाते रहे हैं।

## यूनियनों को मौद्रिक नीति की परवाह क्यों करनी चाहिए

मौद्रिक नीति को यूनियन के अभियानों में शायद ही कभी शामिल किया जाता है। लेकिन इसे शामिल करना चाहिए। मौद्रिक नीति तटस्थ नहीं होती है, वितरण पर इसका भारी प्रभाव होता है। जब केंद्रीय बैंक जानबूझकर अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर निकाल लेते हैं, तो कर्ज लेने की लागत (ब्याज दरें) बढ़ जाती है। इस प्रकार, इस तरह की कार्रवाइयां व्यावसायिक गतिविधि को बाधित करती हैं, श्रम की मांग में कमी पैदा करती हैं, नौकरियों की संख्या को कम करती हैं, तथा मजदूरी और श्रमिकों की सौदेबाजी की ताकत में कमी करती हैं।

अमीर लोग आम तौर पर लेनदार या निवेशक होते हैं; उनके बैंक खातों में बड़ी रकम भी जमा होती है। श्रमिक आम तौर पर कर्जदार या शुद्ध देनदार होते हैं। इसलिए, उच्च ब्याज दरों से धनी निवेशकों को लाभ मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने ऋण लिया है, उनकी लागत और भी अधिक हो जाएगी।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मजदूरी अधिक होने से मुद्रास्फीति होने लगती है। जब सरकारों पर मुद्रास्फीति की दरें कम रखने का जूनून सवार होता है, तब वे श्रम की सौदेबाजी की ताकत को कम करने के लिए कार्य करती हैं। वे इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी को सीमित करती हैं, बेरोजगारी में वृद्धि करती हैं और यूनियनों का गठन और सामूहिक सौदेबाजी को और अधिक कठिन बनाती हैं। लेकिन वे सीईओ के वेतन और पारिश्रमिक पैकेज को कभी भी सीमित नहीं करती हैं।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि हाल के दशकों में कर्मचारियों के वास्तविक टेक-होम वेतन में लगातार गिरावट या ठहराव आया है जबकि सीईओ के वेतन पैकेज में वृद्धि जारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, वर्ष 1979 और महामारी के बीच, सीईओ के वेतन में 940% की वृद्धि हुई; जबकि श्रमिकों के वेतन में केवल 12% की ही वृद्धि हुई।<sup>3</sup> वर्ष 2021 में सीईओ और अमेरिकी श्रमिकों के बीच वेतन अंतर बढ़कर 670-और-1 हो गया।<sup>4</sup>

मुद्रास्फीति के लिए श्रमिकों को दोष देना इस तथ्य को अनदेखा करता है कि जब एकाधिकारी शक्ति वाले बड़े निगम अपना लाभ मार्जिन बढ़ाते हैं तो कीमतें भी बढ़ सकती हैं।<sup>5</sup> वर्तमान मुद्रास्फीति उछाल के कारण रिकॉर्ड कॉर्पोरेट लाभ उत्पन्न हुए हैं,<sup>6</sup> जबकि श्रमिकों को जीवन यापन के खर्च में कटौती की मार झेलनी पड़ रही है।

मजदूरी में वृद्धि से प्रेरित मुद्रास्फीति खराब नहीं होती है यदि इससे श्रमिकों को अधिक क्रय शक्ति मिलती है और घरेलू ऋण में कमी होती है, इस प्रकार अधिक व्यवसाय उत्पन्न होता है। लेकिन अधिकांश देशों में मजदूरी मुद्रास्फीति के अनुपात में नहीं रही है और शायद ही यह इसका कारण रही है। इस प्रकार कम वेतन-अधिक कर्ज-कमजोर कम विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं का एक दुष्चक्र मौजूद है।



<sup>3</sup> मिशेल, एल एंड वोल्फ जे 2019, सीईओ के वेतन में 1978 के बाद से 940% की वृद्धि हुई है, इकोनॉमिक पालिसी इंस्टीट्यूट, 9 जून 2022 को देखा गया <<https://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/>>

<sup>4</sup> रुशे डी 2022, 'अध्ययन में पाया गया कि, सीईओ और अमेरिकी कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर पिछले साल 670 और 1 तक पहुंच गया है', द गार्जियन, 7 जून, 9 जून 2022 को देखा गया <<https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/07/us-wage-gap-ceos-workers-institute-for-policy-studies-report>>

<sup>5</sup> बिबेन्स जे 2022, कॉर्पोरेट मुनाफे ने मुद्रास्फीति में बेढंगा योगदान दिया है। नीति निर्माताओं की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए?, इकोनॉमिक पालिसी इंस्टीट्यूट, 9 जून 2022 को देखा गया <<https://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-disproportionately-to-inflation-how-should-policymakers-respond/>>

<sup>6</sup> मार्टिन एम (रिपोर्टर) 2022, 'अर्थशास्त्री बढ़ती मुद्रास्फीति के बावजूद रिकॉर्ड कॉर्पोरेट मुनाफे की व्याख्या करते हैं', एनपीआर, 13 फरवरी, पॉडकास्ट, 9 जून 2022 को देखा गया <<https://www.npr.org/2022/02/13/1080494838/economist-explains-record-corporate-profits-despite-rising-inflation>>

## नवउदारवादी मौद्रिक नीति की पहचान कैसे करें

नवउदारवादी मौद्रिक नीति अब इतनी आम हो चुकी है कि इस पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है। नवउदारवादी नीति मुख्य रूप से देश की मुद्रास्फीति दर को एक निश्चित निम्न-सीमा के भीतर रखने पर केंद्रित होती है – एक नीति जिसे मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (आईटी) के नाम से जाना जाता है। यह निम्न सीमा में रखने का लक्ष्य आम तौर पर धनी देशों के लिए 2% से कम और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए 5% से कम माना जाता है। आईटी मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है, जबकि नौकरियों, जलवायु, गरीबी, असमानता या सतत विकास जैसे जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करती है।

जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम करना चाहते हैं, तो वे आम तौर पर आधार या नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि करके, सरकारी खर्च को कम करने के लिए बांड बेचकर और सरकारी बांड नहीं खरीदकर, या नियमों में आरक्षित कोष को बढ़ाकर पैसे को अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल लेते हैं। इसका सबसे आम तरीका है ब्याज दरों में वृद्धि करना।

यह नवउदारवादी दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि सरकारी ऋण का स्रोत चाहे कोई भी हो और ऋण का उपयोग चाहे जिस लिए किया जाए, यह आर्थिक विकास के लिए एक खराब चीज है और इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आईएमएफ ऋण-से-जीडीपी का अनुपात अमीर देशों के लिए 60% और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए 40% रखने को बढ़ावा देता है। प्रचलित नवउदारवादी मौद्रिक नीति इससे अधिक किसी भी ऋण-से-जीडीपी अनुपात को विकास के लिए हानिकारक मानती है। नवउदारवादी मौद्रिक नीति आमतौर पर नवउदारवादी राजकोषीय नीतियों के साथ आती है जिसमें सरकारों के बजट घाटे को कम करना, सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च में कटौती और करों में कटौती शामिल है।

नवउदारवादी मौद्रिक नीति के पैरोकार इस बात पर जोर देते हैं कि मौद्रिक प्राधिकरण सरकारी कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, या राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। वे बैंकों को स्वतंत्र और राजनीतिक रूप से तटस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से, कुछ अपवादों के साथ, अधिकांश केंद्रीय बैंकों के नियंत्रणकारी बोर्ड व्यापारिक समुदायों और अभिजात वर्ग के लोगों से बने होते हैं, जो आम तौर पर पूंजी और बैंकरों के हितों को बढ़ावा देते हैं, और नवउदारवादी रूढ़िवाद का पालन करते हैं। केंद्रीय बैंक के बोर्डों में यूनियनों, महिला अधिकारियों के पैरोकारों, स्वदेशी लोगों या कम आय वाले समुदायों के लोगों में से भागीदारी दुर्लभ रही है, जो किसी देश की मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

## नवउदारवादी मौद्रिक नीति की समस्याएं

ऐसा कोई सबूत या शोध नहीं है जो दर्शाता है कि कम मुद्रास्फीति अच्छी है या आर्थिक विकास में योगदान करती है।<sup>9</sup> ऐसा लगता है कि 2% का लक्ष्य 1980 के दशक में न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री द्वारा रैंडम तरीके से 'दो' नंबर को चुने जाने के परिणामस्वरूप उभरा और लोकप्रिय हो गया है।<sup>10</sup> आईएमएफ द्वारा किए गए शोध सहित अन्य शोधों में पाया गया है कि जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, तब भी देश सकारात्मक आर्थिक विकास का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि, इससे कम मुद्रास्फीति दर को केंद्रीय लक्ष्य बनाए रखने का जुनून समाप्त नहीं हुआ, और इसे आईएमएफ भी प्रोत्साहित करता है।

ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित होता है कि केंद्रीय बैंकों से सरकार द्वारा उधार लेने या वित्त प्राप्त करने से मुद्रास्फीति बढ़ती है।<sup>11</sup> ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता है कि एक विशेष ऋण-जीडीपी अनुपात किसी देश के आर्थिक विकास की गारंटी है या जो इसे नुकसान पहुंचा सकता है।<sup>11</sup> वास्तव में, कई देशों के लिए, घाटे की अर्थव्यवस्था या केंद्रीय बैंकों से अधिक कर्ज या वित्त पोषण लेना देश की राजकोषीय नीति का समर्थन करने में मदद कर सकता है।

<sup>9</sup> वह दर जिस पर खुदरा बैंक अपने नकद भंडार को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंकों से रातोंरात उधार लेते हैं।

<sup>10</sup> चौधरी, ए 2022, पृष्ठ 32–34

<sup>11</sup> चौधरी, ए, सुंदरम, जे के 2022, 'मुद्रास्फीति लक्षित वूडू', आईपीएस न्यूज, 1 मार्च, 7 जून को देखा गया, <<https://www.ipsnews.net/2022/03/inflation-targeting-woodoo/>>; इरविन, एन 2014, 'कीवी और मुद्राओं की: कैसे 2: मुद्रास्फीति लक्ष्य वैश्विक आर्थिक सुसमाचार बन गया', द न्यूयॉर्क टाइम्स, 19 दिसंबर, 7 जून 2022 को देखा गया <<https://www.nytimes.com/2014/12/21/upshot/of-kiwis-and-currencies-how-a-2-inflation-target-became-global-economic-gospel.html>>.

<sup>10</sup> चौधरी, ए 2022, पृष्ठ 31–32

<sup>11</sup> चौधरी, ए 2022, पृष्ठ 26–30

वास्तव में, मुद्रास्फीति अक्सर युद्ध, महामारी, जलवायु संकट या मालों की कमी जैसे बाहरी कारकों के कारण पैदा होती है। इस समय यह महामारी, यूक्रेन में युद्ध और जलवायु से सम्बंधित कई घटनाओं के परिणामस्वरूप आपूर्ति की कमी के कारण हो रहा है। ब्याज की उंची दरें उन कारकों को नहीं रोक सकती हैं, केवल जीवन यापन खर्च बढ़ने की समस्याओं को पैदा करेंगी। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो अमीर खर्च करना बंद नहीं करते हैं, केवल सीमित बजट वाले श्रमिक और उनके परिवार के लोग ही खर्च में कटौती करते हैं।

शोध में पाया गया कि मुद्रास्फीति—लक्षित मौद्रिक नीति ढांचे से वेतन हिस्सेदारी में गिरावट आती है।<sup>12</sup> इसलिए, नवउदारवादी मौद्रिक नीति— मुद्रास्फीति के स्तर को कम रखने के अपने एकमात्र उद्देश्य और रोजगार, मजदूरी, गरीबी, या असमानता के प्रति उपेक्षा के कारण— अंत में मुद्रास्फीति की किसी भी वृद्धि के लिए समायोजन के बोझ को उत्पादन और रोजगार पर (अर्थात्, कामगार की नौकरी और कामगारों के वेतन पर) स्थानांतरित कर देती है।

## रोजगार परक न्यायसंगत बहाली के लिए प्रगतिशील मौद्रिक नीति के विकल्प और उदाहरण

वर्तमान नवउदारवादी मौद्रिक नीति के विकल्प आवश्यक और संभव दोनों हैं, और सहायक व्यापक आर्थिक नीतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्ताव के आह्वान के अनुरूप होंगे जो “बेहतर भविष्य का निर्माण” करते हैं और व्यापक—आधार वाली, रोजगार परक बहाली की दिशा में ले जाते हैं।

हम जानते हैं कि विकल्प संभव हैं क्योंकि कई देशों ने अतीत में प्रगतिशील नीतियां अपनाई हैं। वास्तव में, चूंकि आईटी का आविष्कार केवल 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था, उन अमीर देशों को उन मौद्रिक नीतियों का लाभ मिला था, जो औद्योगिकीकरण के साथ—साथ रोजगार में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते थे और अपनी वर्तमान संपत्ति और विकास के स्तर को हासिल किया था। और फिर भी आईएमएफ जैसी संस्थाएं कम आय वाले देशों में आज समान मौद्रिक नीतियों को लागू करने से इनकार करती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि मुद्रास्फीति के स्रोतों की परवाह किए बिना तीन दशकों से अधिक समय तक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की पैरवी करने के बाद आईएमएफ ने लगता है हाल ही में अपनी स्थिति बदल दी है। आईएमएफ ने हाल के एक ब्लॉग<sup>13</sup> में कहा कि देशों को बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन “सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करना” उनके लक्ष्य में शामिल होना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपायों के द्वारा समर्थन दिया जाए। इसने यह भी कहा, कि कीमतों को कम रखने के प्रयास राष्ट्रीय बजट के लिए महंगे पड़ते हैं और “ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से ऊर्जा के अधिक कुशल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होने से अधिक कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा”। राष्ट्रों को ऊर्जा फर्मों के अतिरिक्त लाभ पर स्थायी कर लगाना चाहिए।



<sup>12</sup> रोचॉन, एल-पी और रॉसी, एस 2006, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, आर्थिक प्रदर्शन, और आय वितरण: एक मौद्रिक मैक्रोइकोनॉमिक्स विश्लेषण, जर्नल ऑफ पोस्ट केनेसियन इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 28, सं. 4 (ग्रीष्मकालीन), पृष्ठ 615–638।

<sup>13</sup> अमग्लोबेली एट. अल 2022, ‘रिस्पांस टू हाई फूड, एनर्जी प्राइसेज शुड फोकस ऑन मोस्ट वल्वरेबल’, आईएमएफ ब्लॉग, 7 जून, 7 जून 2022 को देखा गया <https://blogs.imf.org/2022/06/07/response-to-high-food-energy-prices-should-focus-on-most-vulnerable>



## विकास उद्देश्यों को मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्थापित करना

मौद्रिक नीतियों को सतत विकास उद्देश्यों की एक श्रृंखला का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिसमें पूर्ण रोजगार, उचित कार्य, असमानता में कमी और जलवायु सम्बंधित कार्रवाई शामिल है।

ऐतिहासिक रूप से, केंद्रीय बैंकों की भूमिका मुख्य रूप से विकास परक थी और उन्होंने सार्वजनिक निवेश के लिए वित्तपोषण प्रदान किया। दुनिया के दो सबसे पुराने केंद्रीय बैंक – बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्वीडन का रिक्सबैंक – मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के अलावा अन्य विकास परक प्राथमिकताओं को सख्ती से बढ़ावा देने से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं और विकास के वित्तपोषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, रिक्सबैंक सक्रिय रूप से सभी के लिए आवास को बढ़ावा देता रहा है,<sup>14</sup> जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड औद्योगिक और वाणिज्यिक वित्त निगम, और बैंकर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी जैसे विशिष्ट विकास संस्थानों का बीड़ा उठाए हुए था। बांग्लादेश बैंक एक विकास परक केंद्रीय बैंक के रूप में मूल्य स्थिरता और समावेशी विकास की दोहरी जिम्मेदारी भी उठा रहा है। समावेशी विकास में इसका योगदान वित्तीय समावेशन जैसे कृषि क्षेत्र की ऋण नीति, बटाईदारों के लिए ऋण कार्यक्रम और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सामने आता है। बांग्लादेश बैंक वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में ऋण देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुनर्वित्त लाइनों की शुरुआत करके पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को भी बढ़ावा देता रहा है। इसलिए सरकार के विकास लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करने में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण की भी भूमिका हो सकती है।

## मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (आईटी) पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें

मौद्रिक अधिकारियों को मुद्रास्फीति के प्रति अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मुद्रास्फीति की दरों में हर वृद्धि के सामने मुद्रा की आपूर्ति को कड़ा करने से बचना चाहिए। आईटी से दूर जाकर, सरकारें अधिक लचीली राजकोषीय नीतियां अपना सकती हैं, जहां सरकार आर्थिक मंदी से बचने के लिए खर्च कर सकती है, और इस प्रकार अपने लोगों की नौकरियों, मजदूरी और जरूरतों की रक्षा करने में सक्षम हो सकती है।

### यह कहाँ किया गया है:

बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ब्याज दरों में वृद्धि करके मौजूदा वैश्विक मुद्रास्फीति की वृद्धि का जवाब नहीं दे रहा है। इसके बजाय, यह अर्थव्यवस्था को कोविड-19-प्रेरित मंदी से उबरने में मदद करने के लिए धैर्यपूर्वक शक्तिशाली मौद्रिक सहजता से चिपका हुआ है। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने कहा, "हम अनिवार्य रूप से केवल कीमतों में वृद्धि के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम कॉर्पोरेट मुनाफे, नौकरियों और मजदूरी में वृद्धि के साथ बढ़ती कीमतों का एक अच्छा चक्र बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं।"<sup>15</sup>



<sup>14</sup> मेगाव, एन 2017, 'स्वीडिश घरों की कीमतों में मंदी स्थिरता के लिए 'सकारात्मक' है – रिक्सबैंक', फाइनेंशियल टाइम्स, 22 नवंबर, 7 जून 2022 को देखा गया <<https://www.ft.com/content/4f521645-b8fe-3491-983b-9271c4c4dbf16>>.

<sup>15</sup> काजिमोटो टी 2022, 'बीओजे कुरोदा शक्तिशाली सहजता से जुड़ा रहता है, मुद्रास्फीति को अल्पकालिक मानता है', रायटर, 30 मई, 7 जून 2022 को देखा गया <<https://www.reuters.com/business/bojskuroda-vows-patiently-continue-powerful-monetary-easing-2022-05-30>>

## राष्ट्रीय सरकार को अपने केंद्रीय बैंक से उधार लेने या वित्तपोषण प्राप्त करने की अनुमति देना

राष्ट्रीय सरकारों को अपनी वित्तीय गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय बैंक जैसे घरेलू स्रोतों से उधार लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। यह विशेष रूप से तब आवश्यक होता है अगर घरेलू उधार सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए किया जाता है जो विकास में सहायता करेगा और अंततः राजस्व में वृद्धि करेगा। घरेलू ऋण बाहरी ऋण की तुलना में बेहतर होता है क्योंकि बाहरी ऋण आमतौर पर कमजोरियों से जुड़ा होता है जिससे ऋण संकट और मितव्ययिता का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए, कोई भी नियम और कानून जो सरकार को अपने केंद्रीय बैंक से उधार लेने और वित्त प्राप्त करने से रोकते हैं, और इसलिए सरकारों को अपने खर्च को वित्तपोषित करने के लिए या तो बाहरी ऋण लेने के लिए या वित्त पोषण की कमी के कारण मितव्ययिता लागू करने के लिए मजबूर करते हैं, उनमें संशोधन किया जाना चाहिए।<sup>16</sup>

### यह कहाँ किया गया है:

कोविड-19 महामारी के दौरान, क्रोएशिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और सर्बिया के केंद्रीय बैंकों ने अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा लगाने के लिए सरकारों द्वारा जारी स्थानीय मुद्रा बांड खरीदने के उद्देश्य से संपत्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) शुरू किया। इसी तरह के एपीपी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तुर्की के केंद्रीय बैंकों द्वारा भी शुरू किए गए हैं, जबकि इंडोनेशिया और फिलीपींस ने राहत और बहाली के उपायों को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय बैंकों से सरकारी उधारी पर रोक लगाने वाले कानून को निलंबित कर दिया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी इस तरह की खरीद को प्रतिबंधित करने वाले कानून को दरकिनार करने के लिए एक नए तंत्र के माध्यम से सरकारी बांड खरीद रहे हैं।

## विविधतापूर्ण, लोकतांत्रिक और जवाबदेह मौद्रिक प्राधिकरण

केन्द्रीय बैंकों के बोर्ड में कॉर्पोरेट अर्थशास्त्रियों और बैंकों की भरमार हो गई है। जब मौद्रिक नीति को लाभ वृद्धि की बजाय व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया होता है, तो केंद्रीय बैंक के बोर्डों में ट्रेड यूनियनों, महिला अधिकार समूहों, स्वदेशी लोगों, प्रवासी समूहों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) सहित व्यापार समुदाय के बाहर के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यह विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व केंद्रीय बैंक को विभिन्न मुद्दों पर, चाहे पूर्ण रोजगार हो, महामारी हो, जलवायु परिवर्तन हो, या असमानता हो बेहतर ढंग से विचार करने में सक्षम बनाएगा, और मौद्रिक नीति तैयार करने में मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने के प्रति अत्यधिक पूर्वाग्रह को रोक सकेगा।

यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बैंक संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद को केंद्रीय बैंक के निर्णय और संचालन प्रक्रिया की जांच और निगरानी, तथा केंद्रीय बैंक से सरकारी उधार पर नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए।

### यह कहाँ किया गया है:

केंद्रीय बैंक बोर्डों में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व के उदाहरण:

बॉब हॉक (1973–1978) और बिल केल्टी (1987–1992) रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड में शामिल थे जब वे ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (एसीटीयू) के अध्यक्ष और सचिव थे; एक नारीवादी अर्थशास्त्री मर्लिन वारिंग 2005 से 2009 तक रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के बोर्ड की सदस्य थीं; पीएसआई के अध्यक्ष डेव प्रेंटिस, 2012–2015 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गैर-कार्यकारी निदेशक थे; फ्रांसिस ओ'ग्राडी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस (टीयूसी) के महासचिव अक्टूबर 2020 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गैर-कार्यकारी निदेशक बने; **आयरलैंड के दूसरे सबसे बड़े ट्रेड यूनियन, फोर्सा** के पूर्व महासचिव शै कोडी 1 दिसंबर 2020 से आयरलैंड के सेंट्रल बैंक के आयोग में शामिल हैं।

2020

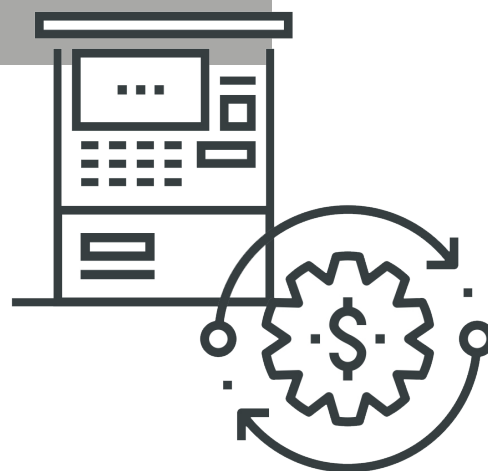
<sup>16</sup> पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल 2020, श्रमिक और ऋण विवरण, 7 जून 2022 को देखा गया <https://publicservices.international/resources/news/debt-briefs---executive-board?lang=en&id=10390&showLogin=true>

कई देशों में केंद्रीय बैंकों की **लोकतांत्रिक निगरानी** का उपयोग किया जाता है:

- बैंक ऑफ इंग्लैंड का कई औपचारिक और अनौपचारिक तंत्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक निरीक्षण किया जाता है, जिसमें संसदीय जांच भी शामिल है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक के गवर्नर और बैंक के अन्य अधिकारियों को ट्रेजरी कमेटी के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जाता है
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) यूरोपीय संघ (टीएफईयू) के कामकाज के बारे में संधि के अनुच्छेद 284 (3) और सेंट्रल बैंक्स की यूरोपीय प्रणाली (ईएससीबी) कानून के अनुच्छेद 15 के अनुसार यूरोपीय संसद के प्रति जवाबदेह है। ईसीबी यूरोपीय संघ के न्यायालय (सीजेईयू) द्वारा न्यायिक समीक्षा के भी अधीन है, जहां अदालत ईसीबी के कृत्यों और निर्णयों की वैधता का निर्णय कर सकती है।

शब्दावली और अन्य पाठ्य सामग्रियों को देखने के लिए इस लिंक पर जाएँ

<https://popshort.link/glossary>



**Public Services International - Asia Pacific**

The global union federation of workers in public services

45 avenue Voltaire, BP 9  
01211 Ferney-Voltaire Cedex  
France

Tel: +33 4 50 40 64 64  
E-mail: [psi@world-psi.org](mailto:psi@world-psi.org)  
[www.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL](http://www.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL)

Public Services International is a Global Union Federation of more than 700 trade unions representing 30 million workers in 154 countries. We bring their voices to the UN, ILO, WHO and other regional and global organisations. We defend trade union and workers' rights and fight for universal access to quality public services.